मध्यप्रदेश : शिक्षा जगत में ऊंची उड़ान के लिए ठोस कदम जरूरी

(राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवम्बर पर विशेष)

- विकास जैन

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर तमाम बहस मुबाहिसों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। वर्ष 2016 में एस्पायरिंग माइंड्स नेशनल इम्प्लॉयबिलिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा इंजीनियर रोजगार पाने लायक नहीं हैं, इन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके बाद कई और भी मौकों पर नियोक्ता कंपनियां अपने कर्मचारियों के मार्फत शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाती रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र के राष्ट्रीय परिदृश्य में मध्यप्रदेश की स्थिति काफी कमजोर है। पिछले पंद्रह सालों से प्रदेश का कोई भी संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान नहीं बना पाया है। इसी साल अप्रैल में मानव संसधान विकास मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग में प्रदेश का कोई भी संस्थान शामिल नहीं हो सका है। यह कचोटने वाली स्थिति है कि मध्यप्रदेश के छात्र अच्छी शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं।

एनआईआरएफ की रैंकिंग की श्रेणियों में देशभर के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों के साथ ही विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फामेर्सी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ के टॉप संस्थान शामिल किया जाता है। राज्य में संचालित एक दर्जन विवि अपना नंबर नहीं लगवा सका। भोपाल के जिन संस्थानों को सूची में शामिल किया गया है। उनमें राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को स्थान दिया गया है। इसमें मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनिट (65वीं रैंक), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट को 60वां स्थान, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को छठवां स्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) को पहली बार 11वीं रैंक हासिल हुई है। शिक्षण और संसाधन, अनुसंधान और कामर्शियल प्रैक्टिस, स्नातक परिणाम, आउटरीच और विशिष्टता और धारणा के आधार पर तैयार की गई है। 2018 के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए 4000 से अधिक संस्थानों ने अपना डेटा जमा किया था। अलग-अलग श्रेणियों में यह रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग का यह चौथा साल है। इसमें भी प्रदेश की एक मात्र राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भी आवेदन किया था। वह भी अपना स्थान रैंकिंग में हासिल नहीं कर सका है।

मैनिट में छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, विकलांगों के लिए अलग से डिजाइन किए गए टॉयलेट्स, रिसर्च प्रोजक्ट्स के साथ ही छात्रों के नवाचार और प्लेसमेंट को भी देखा गया। छात्रों की दी जाने वाली सुविधाओं को भी आधार बनाया गया। 2017 में मैनिट की 74वीं रैंक थी। प्रबंधन ने जी तोड़ मेहनत कि तो 2018 में 55वीं रैंक तक मेनिट पहुंच पाया। इस बार एनआईआरएफ की टीम मैनिट आई तो उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मैनिट की रैंकिंग 10 अंक खिसककर 65 पर पहुंच गई है। आईसर में पीएचडी, रिसर्च वर्क और छात्रों के प्लेसमेंट अच्छा रहा। पिछले तीन सालों में आईसर में प्लेसमेंट बढ़कर न्यूनतम आठ लाख रुपए सालाना हो गया है। आईसर की 2017 में रैंकिंग 98वीं थी, जो 2018 में 56 पर पहुंची। हालांकि इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन रहने के कारण आईसर देशभर में 37 नंबर पर पहुंच गया है। इस बार आईसर को 50.88 प्वाइंट मिले है। इसमें टीचिंग लर्निंग रिसोर्स आदि को भी शामिल किया गया है। उधर, आईआईएफएम देश में वन प्रबंधन पर डिग्री देने वाला प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके बावजूद इसकी रैंकिंग दिनोंदिन विवाद में आने के कारण पिछड़ते जा रहा है। 2017 में आईआईएफएम की रैंकिंग 34वीं थी। जो 2018 में 41वीं हो गई और अब 2019 में 60वीं रैंक पर आईआईएफएम खिसक गया है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नवाचार, रिसर्च वर्क और प्लेसमेंट के आधार पर अंक मिले है, लेकिन इसकी रैंकिंग पिछले साल की मुकाबले पिछड़ गई है। एसपीए को 2018 में आर्किटेक्चर में 5वें नंबर पर रहने वाला ये संस्थान अब छठवें नंबर पर है।

सूबे के कालेजों में प्रवेश की स्थिति पिछले वर्षों की अपेक्षा तेज है, लेकिन इसके बाद भी साढ़े तीन लाख विद्यार्थी 12वीं करने के बाद कालेजों से दूर बने हुए हैं। उक्त विद्यार्थियों का डाटा स्कूल, उच्च, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास तक नहीं हैं। प्रदेश से आठ लाख विद्यार्थियों ने 12वीं पास किया है, सवा लाख विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। एमपी बोर्ड से नियमित पांच लाख 84 हजार 664 और स्वाध्यायी सवा लाख विद्यार्थी 12वीं पास हुए। सप्लीमेंट्री और सीबीएसई से एक लाख विद्यार्थी पास हुए। राज्य से करीब आठ लाख विद्यार्थी कालेजों में प्रवेश लेने की योग्यता रखते हैं। अभी तक उच्च शिक्षा के यूजी कालेजों में सवा चार लाख, इंजीनियरिंग और फार्मेसी में करीब चालीस हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। जबकि एमबीबीए और बीडीएस का आंकड़ा तीन हजार हजार तक नहीं पहुंच सका है। सभी प्रवेश को देखते हुए अभी भी करीब साढ़े तीन लाख विद्यार्थी 12वीं के बाद प्रवेश लेने से वंचित बने हुए हैं। व्यापमं से नर्सिंग और एग्रीकल्चर कालेज में प्रवेश लेने के लिए करीब पचास हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे। आठवीं के बाद जो छात्र अध्ययन नहीं करते उनके लिए आईटीआई जैसे संस्थानों में भेज कर तकनीकी दक्षता में निपुण किया जाये। उदाहरण के लिए चंदेरी के बुनकर परिवार किसी बच्चे की कपड़ा बुनने मे रुचि है तो उसे आधुनिक तकनीक में ट्रेंड किया जाये। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में क्राफ्ट सीखना अनिवार्य किया जाये। इंटर के बाद रुचि के अनुसार शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाये। विवि में डिग्री के लिए पढाई के स्थान पर काम की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाये। विवि अपने क्षेत्र के मानव संसाधन विकास का केंद्र बनें। ऐसी योजना बनाई जाये। काम कठिन अवश्य है पर सरकारें ठान लें तो कोई काम मुश्किल नहीं है।

सरकार ने तमाम विश्वविद्यालय स्थापित किए और कॉलेजों की संख्या भी तेजी से बढ़ाई, लेकिन उनमें न तो मूलभूत सुविधाएं मिली सकीं। ना बिल्डिंग मिली, ना फर्नीचर, ना लैब और ना लाइब्रेरी मिल सकीं। सबसे बड़ी बात ये है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज जाने जाते हैं शिक्षकों के कारण, उनकी पूर्ति अतिथि विद्वानों से की जा रही है। उनके भरोसे कालेज और विश्वविद्यालय चलाए जाते रहे। 2004 से लेकर 2010 तक तीन बार बैकलॉग की पूर्ति के लिए विज्ञापन निकाले, 34 लोग आए, जो क्वालिफाइड नहीं थे। सरकार ने कहा कि आपको क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए समय दिया जाता है फिर भी इनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने ना तो पीएचडी की और ना उस समय प्रचलित एमफिल पूरी कर सके। सरकार का जोर जीआरएस (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) बढ़ाने पर रहा है। एक वक्त यह 8 और 9 में था, जो अब तक 12 तक आ गया है और जबकि देश के अन्य कालेजों अन्य प्रदेशों में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की तुलना में अभी भी मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की कम होती रुचि से निपटने के लिए अनेक उपाय किये गये। आॅनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस साल सरकारी काॅलेजों में सीट की संख्या 25 फीसदी तक बढ़ा दी गई। परिणाम यह हुआ कि प्राइवेट कॉलेज लगभग बंद होने की कगार पर आ गए हैं। एमबीए कोर्स को नकार दिया गया है, तो और लंबे समय के बाद में सरकार ने 2010 में सीधी भर्ती से तीन हजार 25 निकाले थे उनका विवाद अभी थमा नहीं है।

व्यापमं का मामला अभी थमा नहीं है। घोटाले के बारे में सब कुछ जानकारी है। तो हम यदि विचार करें तो सरकार ने 15 साल में योजनाएं बहुत अच्छी और बहुत योजनाएं बनाई लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मध्यप्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहीं बढ़ पाया। व्यापमं घोटाले ने भी मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। यहां के विद्यार्थियों के लिए एक तरह से यह घोटाला अभिशाप के तौर पर सामने आया। मेधावी विद्यार्थियों का बंटाधार इस घोटाले ने किया। अच्छी नौकरियों और बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अवसर तलाशने वाले मध्यप्रदेश के हरेक विद्यार्थी को शंका भरी निगाहों से देखा गया और आज भी देखा जा रहा है। इस कलंक से विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को बचाने के लिए ठोस कदम की दरकार आज भी बनी हुई है।

सरकार ने आज की तारीख में 30 के लगभग निजी विश्वविद्यालय स्थापित करा दिए हैं। अभी और पाइपलाइन में हैं, जिसके पास भी पांच करोड़ नगद था। उन्होंने एफबी जमा करने के बाद बीस हजार वर्गफिट एरिया में कंस्ट्रक्टेड और 20 एकड़ जमीन होने पर एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर लिया। उक्त विश्वविद्यालयों

को स्थापित करने के बाद उनको नियंत्रित करने सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। अब छात्रों की संख्या, परीक्षा, को लेकर मॉनिटरिंग की कार्रवाई चल रही है। राज्यपाल की समीक्षा बैठक होती है गुणवत्ता पर बार-बार निर्देश देते हैं कि ग्रेडिंग के लिए निर्देश देते हैं। प्रदेश में कुछ कॉलेज नैक की ग्रेडिंग में ए ग्रेड में आए हैं। आश्चर्य की बात है कि मेंटर कॉलेज बनने के लिए मध्यप्रदेश में केवल एक सरकारी कालेज टीआरएस कॉलेज रीवा ही चुना गया है। यहां तक कि भोपाल के एक्सीलेंस कॉलेज से तीन बार ग्रेड मिला है। सरकारी कॉलेज में पदों को भरना। लगभग तीन हजार पदों पर भर्ती करने तीन तरह के विज्ञापन निकले गए। उनकी एक समन्वित सूची जारी हुई और सूची को लेकर के 40 से 50 रेट हाईकोर्ट में लग चुकी हैं। कभी कुछ गलती हुई कभी कुछ गलती हुई। अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 15 साल से कालेजों में कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों ने भी नियमितकरण को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। सरकार को ऐसी संबंधित नीति बनानी चाहिए कि प्रतिवर्ष जो नए पद रिक्त हो उनकी भर्ती होती चली जाए और आयोग के माध्यम से भर्ती होती चली जाए। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय पदों की भर्ती करें विश्वविद्यालयों की स्थिति भी है कि विश्वविद्यालयों में चयन समिति का चेयरमैन वाइस चांसलर होता है और चेयरमैन वाइस चांसलर है तो सरकार को चाहिए कि विश्वविद्यालयों के लिए जैसे अन्य प्रदेशों में है और प्राइवेट कॉलेज के लिए जैसे अन्य प्रदेशों में विश्वविद्यालय चयन आयोग और प्राइवेट कॉलेज चयन आयोग शिक्षक चयन आयोग अलग से बनाए जाने चाहिए। उनके माध्यम से यह भर्ती हो। यह सही है कि बिहार, उप्र और उड़ीसा के साथ तमाम जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनकी तुलना में हमारा शिक्षणिक का स्तर थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। इस विस्तार को बनाए रखने के लिए शिक्षकों की प्रतिपूर्ति करनी होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा पाठ्यक्रम अपडेट करना होगा। अब नई सरकार बदलने के बाद में जो पाठ्यक्रम लाए हैं वो 15 साल पुराना पाठ्यक्रम रिपीट कर दिया है। पाठ्यक्रम में खिलवाड़ करते रहते हैं यह उचित नहीं है। पाठ्यक्रमों को अपनी गति से चलाएं। शिक्षकों का दायित्व है कि वह अपने विद्यार्थियों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करके दें।
जहां तक कृषि शिक्षा का प्रश्न है हमारे यहां यद्यपि दो कृषि विश्वविद्यालय हैं। उनसे संबद्ध कालेज भी हैं, लेकिन देखा गया है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालयों का और कृषि शिक्षा का जितना अधिक विस्तार है। वहां सामान्य पाठ्यक्रम वाले कालेजों को भी कृषि विषय दिया जाता है, तो कृषि विषय को जोड़ा गया है। यह एक बड़ा क्षेत्र है। कृषि जिसको मध्य प्रदेश की सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में अभी तक नहीं जोड़ा गया है। सामान्य शिक्षा के लिए कालेजों में कृषि को भी जोड़ना नितांत आवश्यक है। जैसे राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में है। उससे भी विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

मध्यप्रदेश में हर जिले में लगभग चिकित्सा शिक्षा के लिए कालेज खोले जा रहे हैं तो आयुर्वेद की ओर भी ध्यान दिया जाए यहां पर जो होम्योपैथी के तमाम कालेज स्थापित किए हैं। इसी तरह आयुर्वेद के कालेज और आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। राजस्थान और गुजरात में एक-एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय हैं वैसा यहां पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित कराकर आयुर्वेद की पढ़ाई को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत की जलवायु के हिसाब से आयुर्वेद की शिक्षा पद्धति को विकसित करना आवश्यक है तो गांव में चिकित्सकों को नहीं भेज पा रहे हैं तो कम से कम आयुर्वेद के भेज पाएंगे वहां पर आएंगे तो है एक ट्रेनिंग देने के बाद में हर गांव में एक डॉक्टर उपलब्ध हो पाएगा। इससे भी विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी और लोगों को राहत भी मिलेगी।

(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।